

## झारखंड और ओडिशा राज्य..

### बनाम

एम/एस. एल. ए. ओपाला आर. जी. लिमिटेड.

सिविल अपील संख्या 2006 का 2240

मार्च 27 , 2014

जे एल दत्त एवं एस ए बोब्दे , जस्टिस

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956-धारा: 8 (5) (बी)-झारखंड राज्य सरकार में स्थित प्रतिवादी-विक्रेता की औद्योगिक इकाई-कांच के बर्तनों के निर्माण में लगे प्रतिवादी-विक्रेता के निर्माण और प्रयोज्यता के तहत अधिसूचना जारी नं. 25, दिनांक 25. 06. 2001 में यह निर्देश देते हुए कि झारखंड राज्य में व्यापार के किसी भी स्थान से अंतरराज्यीय बिक्री या वाणिज्य के क्रम में सभी प्रकार के कांच और कांच की चादरों की बिक्री के संबंध में देय कर की गणना 3% की दर से की जाएगी। - प्रतिवादी-विक्रेता ने अधिसूचना के तहत कर की कम दर के लाभ का दावा करते हुए कहा कि इसके द्वारा निर्मित कांच के बर्तन कांच का एक रूप हैं और कांच के रूप भी अधिसूचना के दायरे में आते हैं - मूल्यांकन प्राधिकरण ने प्रतिवादी-विक्रेता के रुख को खारिज कर दिया-हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी-विक्रेता द्वारा निर्मित कांच के बर्तन एक प्रकार का कांच हैं और इसलिए, यह अधिसूचना के तहत कर की कम दर का लाभ उठाने का हकदार है - आयोजित: एक अधिसूचना के निर्माण का यह तय नियम है कि शुरुआत में एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि क्या एक डीलर/निर्माता इसके द्वारा बिल्कुल भी कवर किया गया है और यदि डीलर/निर्माता इसके द्वारा बिल्कुल भी कवर किया गया है और यदि डीलर/निर्माता अधिसूचना के भीतर आता है, तो अधिसूचना के प्रावधानों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाए-तत्काल मामले में, राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करते समय अभिव्यक्ति का उपयोग किया: कांच के प्रकार और अभिव्यक्ति "कांच के रूप" नहीं-मूर्तियों पर कर लगाने में शब्दों और अभिव्यक्तियों को उनकी सामान्य और लोकप्रिय बोलचाल में देखा जाना चाहिए, दो शब्द "प्रकार" और "रूप", विशेष रूप से विशिष्ट विशेषता में। जिस तरह से वस्तुएं मौजूद हैं-"कांच के प्रकार" अभिव्यक्ति का उद्देश्य

"कांच के रूपों" को संदर्भित करना या शामिल करना नहीं हो सकता था-प्रतिवादी-विक्रेता द्वारा निर्मित कांच के बर्तन हालांकि कांच से बने होते हैं, उन्हें "कांच का प्रकार" नहीं माना या कहा जा सकता है और चूंकि अधिसूचना में केवल कांच के प्रकारों के कर की दर में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, न कि "कांच के रूपों" के लिए जो प्रतिवादी द्वारा कांच के बर्तन के रूप में निर्मित किया जाता है, प्रतिवादी अधिसूचना-बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग 16 के दायरे में नहीं आएगा।

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड (1990) 4 एस. सी. सी.

256:1990 (2) एस. सी. आर. 659; गैमन (आई) लिमिटेड बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त (2011) 12 एससीसी 499:2011

(7) एससीआर 195; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम

झारखंड राज्य, करतारपुर रोलिंग मिल्स बनाम सीसीई, ईगल

फ्लास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, भारत सरकार बनाम भारतीय

तंबाकू संगठन (2005) 7 एस. सी. सी. 396:2005

(2) पूरक। एससीआर 859; सीमा शुल्क कलेक्टर

(निवारक) बनाम मा/वा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। (2009) 12.

SCC 73 ~: 2009 (2) SCR 120-के लिए संदर्भित।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और मैकनिल/इयान डिक्शनरी-संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ:

1990 (2) एस. सी. आर. 659 पैरा 20

2011 (7) एस. सी. आर. 195 पैरा 21

2005 (2) एस. सी. आर. 859 पैरा 23

2009 (2) एस. सी. आर. 120 पैरा 23

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2006 का 2240।

रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 22.06.2005 के विनिश्चय और आदेश से, डब्ल्यूपी (टी) सं. 2004 का 4572।

जयेश गौरव (कृष्णानंद पांडे के लिए) अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता और रवि भारुका (डॉ. सुशील बलवाड़ा के लिए) उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था |

## आदेश

1. "" "यह अपील झारखंड के उच्च न्यायालय द्वारा रांची में 2004 का डब्ल्यू. पी. [टी] No.4572, दिनांक 22.06.2005 में पारित फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।". विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त देवघर दिनांक 13.05.2004, द्वारा जारी पत्र को रद्द कर दिया है, जहां निर्धारण प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी -विक्रेता के इस मत को खारिज कर दिया है कि वह झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना S.O No.25 (संक्षेप में, "अधिसूचना") दिनांक 25.06.2001, के तहत कर की कम दर का भुगतान करने के लिए योग्य है, और उत्तरदाता-डीलर को 4 प्रतिशत की दर से अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में कर जमा करने का निर्देश दिया।
2. उपरोक्त अधिसूचना पर संभावित विस्तार इस अपील का विषय है।
3. तथ्यों का परिप्रेक्ष्य है: उत्तरदाता-डीलर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया है, जो ओपल ग्लास से बने ग्लास और ग्लासवेयर के निर्माण में लगी हुई है। उत्तरदाता-डीलर की औद्योगिक इकाई झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर में स्थित है।
4. उत्तरदाता-डीलर बिहार वित्त अधिनियम, 1981 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 ("अधिनियम", संक्षेप में) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत डीलर है।

5. राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा 5 के खंड (बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है। चूंकि अधिसूचना का निर्माण जारी है, इसलिए हम अधिसूचना निकालना उचित समझते हैं। यह इस प्रकार है:

"S.O.25, दिनांक 25 जून, 2001-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1958 का अधिनियम 74) की धारा 8एफ की उपधारा (5) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल ने झारखंड राज्य में व्यापार के किसी भी स्थान से अंतरराज्यीय बिक्री या वाणिज्य के दौरान सभी प्रकार के कांच और कांच की चादरों की बिक्री के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या (2) के तहत देय कर की गणना तीन प्रतिशत की दर से की जाएगी और इस संबंध में किसी वैधानिक रूप की आवश्यकता नहीं होगी।

2. यह अधिसूचना 16 जून, 2001 से प्रभावी होगी।।

6. अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, उत्तरदाता-डीलर ने दिनांक 27.05.2002 के पत्र द्वारा अधिनियम के तहत अधिकारियों को सूचित किया था, कि, चूंकि उत्तरदाता-डीलर अधिसूचना द्वारा कवर किया जाएगा, अंतर-राज्यीय बिक्री में कांच के बर्तनों पर देय कर की दर 3 प्रतिशत की दर पर होगी। दुर्भाग्यवश, अधिकारियों ने डीलर द्वारा किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

7. बाद में, अधिकारियों ने प्रत्यर्थी निर्माता को दिनांक 09.01.2004 को एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्हें पंजीकृत और अपंजीकृत डीलरों को क्रमशः 4% और 12% की दर से अंतर-राज्यीय बिक्री से संबंधित लेनदेन के लिए कर जमा करने

का निर्देश दिया गया।। प्रत्यर्थी को यह कारण बताने का भी निर्देश दिया गया कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 16 और 16 (9) के तहत जुर्माना और अधिनियम क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी को पंजीकृत डीलरों को बिक्री के लिए 4% और अपंजीकृत डीलरों को अंतरराज्यीय बिक्री के लिए 12% पर रिटर्न और जमा कर को सही करने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए।।

- 8 . प्रत्यर्थी -विक्रेता ने 16.01.2004 को अपना जवाब दाखिल किया। इसने कहा कि यह अपने उत्पादों के लिए अंतरराज्यीय व्यापार में बिक्री पर 3% कर लगाने और जमा करने के लिए उत्तरदायी था। इसने दावा किया कि रिटर्न सही ढंग से दाखिल किए गए थे और 3% पर कर सही ढंग से जमा किया गया था।।
- 9 . उक्त पत्र/नोटिस जारी किए जाने के बाद अधिकारियों ने दिनांक 13.05.2004 के अपने पत्र में इसके मत को खारिज कर दिया और सूचित किया कि प्रत्यर्थी अपनी अंतर-राज्यीय बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि एक पंजीकृत डीलर को किया जाता है और 12 प्रतिशत की दर से एक अपंजीकृत डीलर को किया जाता है।
- 10 . इसके अलावा, प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ता को अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था कि उसके द्वारा निर्मित उत्पाद कांच के बर्तन हैं और इसलिए, दिनांक 13.07.2004 के पत्र द्वारा अधिसूचना के तहत शामिल नहीं हैं।

11. प्रत्यर्थी -विक्रेता ने दिनांक 09.01.2004,13.05.2004 और 13.07.2004 के संचारों से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया था कि वह उपरोक्त पत्रों को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करे और अधिनियम के तहत अधिकारियों को अधिसूचना का लाभ बढ़ाने का निर्देश दे, जो 16.06.2001 से प्रभावी हो गया है।

12. उच्च न्यायालय ने, उनके सामने मुद्दे पर विस्तार से विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उत्तरदाता-डीलर द्वारा निर्मित कांच का बर्तन एक प्रकार का कांच है और इसलिए, यह अधिसूचना के तहत टैक्स की कम दर के लाभ का हकदार है और, तदनुसार, उक्त पत्रों को रद्द कर दिया है।

13. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, राज्य, इस अपील में हमारे समक्ष है।

14. "" हमने श्री जायेश गौरव, अपीलार्थी-राज्य के विद्वान वकील और श्री एस डी को सुना है। संजय, प्रत्यर्थी -विक्रेता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील। हमने अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों और इसमें आक्षेपित निर्णय और आदेश का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

15. श्री गौरव प्रस्तुत करेंगे कि अधिसूचना में उपयोग किए गए "कांच के प्रकार"

अभिव्यक्ति में विचाराधीन उत्पाद शामिल नहीं होगा क्योंकि यह केवल "कांच का रूप" है। वह हमें नौ प्रकारों में वर्गीकृत किए जाने वाले ग्लास के प्रकारों के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान करते थे: 1) सोडा ग्लास या सोडा-लाइम ग्लास, 2) रंगीन ग्लास, 3) प्लेट ग्लास, 4) सेफ्टी ग्लास, 5) लैमिनेटेड ग्लास, 6) ऑप्टिकल ग्लास, 7) पायरेक्स ग्लास, 8) फोटो-क्रोमेटिक ग्लास, और 9) लीड क्रिस्टल ग्लास। इसलिए वह तर्क देंगे कि उत्पाद, "कांच के बर्तन" उपरोक्त प्रकार के कांच में से कोई नहीं है, बल्कि कांच का एक अन्य रूप है जो अधिसूचना के लाभ का हकदार नहीं होगा और उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में गलती की है।

16. श्री एस. डी. संजय, विद्वान वरिष्ठ वकील उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को सही ठहराते हैं और उसे प्रस्तुत करते हैं उत्तरदाता-डीलर के उत्पादों को अधिसूचना द्वारा कवर किया जाता है क्योंकि "कांच के बर्तन" वह उत्पाद है जिसमें विभिन्न घटकों को एक साथ फ्यूज किया जाता है ताकि कांच को उस सांचे के अनुसार अंतिम रूप दिया जा सके जिसमें वे निर्मित होते हैं, जैसे क्रॉकरी, फूलदान, आदि। और इसलिए, "कांच के प्रकार" की श्रेणी में आते हैं "" "वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि कानूनों पर कर लगाने में, आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन देने की प्रकृति की एक अधिसूचना का उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक उद्देश्यपूर्ण

व्याख्या दी जानी चाहिए।" ""

17. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में विचार करने और निर्णय लेने वाला मुख्य मुद्दा वह व्याख्या है जो अधिनियम की धारा 8 (5) (बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताए गए "कांच और कांच की चादरों के प्रकार" शब्द को दी जा सकती है।
18. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के विषय पर ध्यान देना प्रासंगिक है। अधिसूचना का विच्छेदन निम्नलिखित को इंगित करेगा, अर्थात्:
- a) झारखंड के राज्यपाल ने अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) के खंड (बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है;
- b) अधिसूचना अधिनियम के तहत कर की दर में कमी की बात करती है;
- c) टैक्स की दर 4 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दी गई है;
- d) अधिसूचना में आगे यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत पंजीकृत डीलरों को बनाए गए ग्लास और ग्लास-शीट के प्रकारों की बिक्री के लिए किसी वैधानिक फॉर्म की आवश्यकता नहीं है;
- e) अगर "सभी तरह के ग्लास और ग्लास-शीट" की बिक्री अपंजीकृत डीलरों को की जाती है, तो टैक्स की दर 12 प्रतिशत होगी।
19. हम विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस. डी. द्वारा रखे गए प्रस्ताव से सहमत नहीं

हैं, कि उनके तर्क के समर्थन में कर प्रोत्साहन देने वाली अधिसूचना की उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए। यह एक अधिसूचना के निर्माण का तय नियम है कि शुरुआत में एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि क्या कोई डीलर/निर्माता इसके द्वारा बिल्कुल भी कवर किया गया है और यदि डीलर/निर्माता अधिसूचना के भीतर आता है, तो अधिसूचना के प्रावधानों का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ।

20. शाब्दिक रूप से, छूट किसी भी दायित्व, कर या शुल्क के भुगतान से स्वतंत्रता है। यह अलग-अलग अनुप्रयोगों को मान सकता है।

एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जैसे कि नई इकाइयों के लिए कर अवकाश का प्रावधान, विशिष्ट शर्तों के तहत सीमित अवधि के लिए वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए कर की रियायती दर और इसलिए, *भारत संघ बनाम वुड पेपर्स लिमिटेड*, (1990) 4 एससीसी 256 इस न्यायालय ने कहा है कि शुल्क प्रावधान के विपरीत छूट अधिसूचना या छूट खंड के निर्माण का परीक्षण अलग-अलग कसौटी पर परीक्षण किया जाना चाहिए और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि छूट अधिसूचना के संबंध में पात्रता खंड को सख्त अर्थ दिया गया है और अधिसूचना की व्याख्या इसकी भाषा के संदर्भ में की जानी चाहिए, हालांकि,, एक बार जब कोई निर्धारित पात्रता खंड को संतुष्ट कर देता है, छूट खंड का शाब्दिक अर्थ लगाया जा सकता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित के रूप में उक्त

दृष्टिकोण को अपनाने के तर्क की व्याख्या की है:

4. . वास्तव में एक छूट प्रावधान एक अपवाद की तरह है और निर्माण या कानूनों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत पर इसका सख्ती से या तो विधायी इरादे या असमान बोझ के आर्थिक औचित्य या राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोषीय प्रावधानों के प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण अर्थ लगाया जाता है। लेकिन एक बार अपवाद या छूट लागू हो जाने के बाद किसी भी नियम या सिद्धांत के लिए इसे सख्ती से समझने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में एक छूट प्रावधान के उदार और सख्त निर्माण को व्याख्या करने के विभिन्न चरणों में लागू किया जाना है। जब सवाल यह होता है कि क्या कोई विषय अधिसूचना में आता है या छूट खंड में आता है, तो इसे अपवाद की प्रकृति में होने के कारण सख्ती से और विषय के खिलाफ समझा जाना चाहिए, लेकिन एक बार जब प्रयोज्यता के बारे में अस्पष्टता या संदेह दूर हो जाता है और विषय अधिसूचना में आ जाता है, तो इसे पूरी छूट दी जानी चाहिए और यह एक व्यापक और उदार निर्माण की मांग करता है।

21. इस कोर्ट में *गैमन (आई) लिमिटेड वी. कमर सीमा शुल्क का*, (2011) 12 एससीसी 499 अपीलार्थी की याचिका को अस्वीकार करते हुए कि छूट अधिसूचना को अंतर्निहित उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए।

नोवोपान इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें उपर्युक्त सिद्धांत और कर से छूट या अपवाद का दावा करने के लिए पात्रता निर्धारित करने में शाब्दिक व्याख्या को अपनाने के पीछे का उद्देश्य इस प्रकार निम्नलिखित है:

" 16 . . सिद्धांत है कि अस्पष्टता के मामले में, एक कर कानून को निर्धारिती के पक्ष में माना जाना चाहिए-यह मानते हुए

कि उक्त सिद्धांत अच्छा और सही है-एक अपवाद या छूट देने वाले प्रावधान के निर्माण पर लागू नहीं होता है; उन्हें सख्ती से समझना होगा। " एक व्यक्ति जो उसे कर देयता से मुक्त करने के लिए एक अपवाद या छूट प्रावधान का आह्वान करता है, उसे स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान द्वारा कवर किया गया है। संदेह या अस्पष्टता के मामले में, इसका लाभ राज्य को मिलना चाहिए। यह मैंगलोर केमिकल्स और अन्य निर्णयों में समझाया गया कारण है। इस तरह के प्रत्येक अपवाद/छूट से समुदाय के अन्य सदस्यों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। एक बार, निश्चित रूप से, प्रावधान उस पर लागू पाया जाता है, तो इसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। " जैसा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा देखा गया है *हंसराज गोरधंडास वी. " सीसीई और सीमा शुल्क* कि इस तरह की अधिसूचना की व्याख्या शब्दों के आलोक में की जानी चाहिए | इसके द्वारा नियोजित है और किसी अन्य आधार पर नहीं। यह सिद्धांत के संदर्भ में इस तरह से आयोजित किया गया था कि एक कर कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, यह शब्द शब्दों के स्पष्ट अर्थ के लिए होना चाहिए और यह कि मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा यानी छूट की साधारण शर्तों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए।

(जोर दिया गया)

22. इन *सीसीई वी. " महान डेयरीज* इस न्यायालय ने कहा है:

" 8 . यह तय किया गया कानून है कि अधिसूचना के लाभ का दावा करने के लिए, एक पार्टी को अधिसूचना की शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर अधिसूचना के शब्दों पर लाभ उपलब्ध नहीं है, तो अधिसूचना के शब्दों को फैलाकर या अधिसूचना में शब्द जोड़कर लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।

23. " *सीसीई वी. " भल्ला एंटरप्राइजेज* एक प्रस्ताव रखा गया है कि

उपयोग की गई भाषा के आधार पर अधिसूचना का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

इसी तरह का विचार इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा व्यक्त किया गया

है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एलटीडी बनाम " झारखंड राज्य, कर्तार रोलिंग मिल्स बनाम सीसीई, ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड वी. " सीसीई, सरकार ऑफ इंडिया वी. इंडियन टोबैको एसोसिएशन, (2005) 7 एससीसी 396, सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक) वी. मालवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2009) 12 एससीसी 735 और सीसीई वी. " रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स "

24. "" "यह कहते हुए, अब हम जांच करेंगे कि क्या यह अधिसूचना विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर बिल्कुल भी लागू होगी।" ""

25. तत्काल मामले में, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और "ग्लास के प्रकार" अभिव्यक्ति का उपयोग किया है न कि "ग्लास के रूप" अभिव्यक्ति का इसलिए, इसलिए, इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या दोनों शब्द अपने अर्थ और महत्व में समान होंगे।

26. यह एक तय किया गया कानून है कि कानूनों पर कर लगाने में नियम और अभिव्यक्तियां होनी चाहिए उनकी सामान्य और लोकप्रिय बोलचाल में देखा गया और उनके वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। आम बोलचाल में, दो शब्द "प्रकार" और "रूप" एक समान नहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, जबकि अभिव्यक्ति "प्रकार" का अर्थ है "प्रकार, वर्ग, नस्ल, समूह, परिवार, जीनस"; "रूप" शब्द का अर्थ है "किसी चीज़ का दृश्य आकार या विन्यास" या "किसी कलात्मक कार्य में शैली, डिजाइन और व्यवस्था जो इसकी सामग्री से अलग है। इसी तरह, मैकमिलियन डिक्शनरी "टाइप" को "समान गुणों

या विशेषताओं वाले लोगों या चीजों के समूह के रूप में परिभाषित करती है जो उन्हें अन्य समूहों से अलग बनाते हैं" और "रूप" को "विशेष तरीके से जिसमें कुछ प्रकट होता है या मौजूद होता है या किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का आकार होता है" के रूप में परिभाषित करता है" | " इसलिए, "प्रकार" वर्गीकृत किए जाने वाले आइटम की व्यापक प्रकृति पर आधारित होते हैं और "रूपों" के संदर्भ में, विशिष्ट विशेषता उस विशेष तरीके से होती है जिसमें आइटम मौजूद होते हैं। एक उदाहरण आइटम "वैक्स" हो सकता है। मोम के प्रकारों में पशु, सब्जी, पेट्रोलियम, खनिज या सिंथेटिक मोम शामिल होंगे जबकि मोम का रूप मोमबतियां, स्नेहक मोम, सीलिंग मोम आदि हो सकता है।

27. मान लीजिए, कांच के बर्तन कांच का एक रूप है और निर्धारिती द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कांच के रूप भी उक्त अधिसूचना द्वारा कवर किए जाते हैं। कांच के बर्तन शब्द में आम तौर पर कांच से बने आभूषण, वस्तुएं और वस्तुएं शामिल होती हैं। द न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द मरियम-वेबस्टर डिक्शनरी और द मैकमिलियन डिक्शनरी इसे परिभाषित करते समय उक्त सामान्य अर्थ का उल्लेख करते हैं। कांच के बर्तनों में क्रॉकरी जैसे पीने के बर्तन (पीने के बर्तन) शामिल होंगे और टेबलवेयर और सामान्य कांच की वस्तुएं जैसे कि फूलदान, बर्तन आदि। इसलिए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि

अभिव्यक्ति ग्लास के प्रकार का उद्देश्य ग्लास के रूपों को संदर्भित करना या शामिल करना हो सकता है।

28. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी -डीलर कांच के बर्तनों का निर्माता है। हमारे विचार में, उत्तरदाता-डीलर द्वारा निर्मित कांच के बर्तन, हालांकि कांच से बने होते हैं, को उपरोक्त चर्चा के आलोक में कांच के प्रकार के रूप में नहीं माना जा सकता है या कहा नहीं जा सकता है और चूंकि अधिसूचना में केवल कांच के प्रकारों के कर की दर में कमी का प्रावधान है, न कि कांच के रूपों के लिए जो उत्तरदाता द्वारा कांच के बर्तन के रूप में निर्मित किया जाता है, उत्तरदाता अधिसूचना द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि उत्तरदाता-डीलर, कांच की वस्तुओं का निर्माता, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.06.2001 को जारी अधिसूचना का लाभ लेने का हकदार नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को बनाए नहीं रख सकते।

29. परिणाम में, हम इस अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

30 . चूंकि मामला काफी समय से लंबित था, इसलिए हम अपीलकर्ताओं को निर्देश देते हैं कि वे केवल आकलन वर्षों 2002-2003 से 2005-2006 के लिए देय कर के अंतर की वसूली करते समय जुर्माना न लगाएं।

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। तदनुसार आदेश दिया गया।

“जस्टिस  
(एच. एल. दत्त)

जस्टिस "  
(एसए बोब्दे)

नई दिल्ली; 27 मार्च, 2014.

यह अनुवाद पीयूष आनन्द, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।